राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एकल पीठ आपराधिक विविध (याचिका) नंबर 6269/2021

रजनीश कुमार मीना पुत्र धुलेश्वर मीना, आयु लगभग 26 वर्ष, बी/सी मीना, पुत्र किकावत फला रकड़ा, ऋषभदेव, उदयपुर (राज)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा लोक अभियोजक

2. जीवतराम मीना पुत्र सावजी मीना, आयु लगभग 60 वर्ष, बी/सी मीना, पुत्र बिलख फला रकदा किकावत, पुलिस थाना ऋषभदेव, उदयपुर (राज.)

---- शिकायतकर्ता/उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री राम सिंह रावल

उत्तरदाता(गण) के लिए : श्री एस के भाटी, पीपी

माननीय श्री न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

दिनांक 08/12/2021

वर्तमान आपराधिक विविध याचिका विशेष न्यायालय, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, संख्या 1, उदयपुर (इसके बाद 'विचारण कोर्ट' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया। आरोपी-याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पीड़िता पी.डब्ल्यू.2 मास्टर एम से जिरह सुरक्षित रखने की मांग की। पी.डब्ल्यू.2 एम को रुखसत कर दिया। सीआरपीसी की धारा 309 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा एम से जिरह करने से रोक दिया गया।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पुलिस स्टेशन ऋषभदेव, उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/2020 के अनुसरण में वर्तमान याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया गया था और विशेष न्यायालय, पॉक्सो अधिनियम 1, उदयपुर द्वारा भा.दं.सं. की धारा 363,376,344 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

मुकदमे के दौरान, पीड़िता मास्टर एम दिनांक 29.09.2021 को विचारण कोर्ट के समक्ष अभियोजन गवाह पी.डब्ल्यू.2 के रूप में पेश हुआ। पी.डब्ल्यू. की मुख्य परीक्षा के पूरा होने के बाद, आरोपी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया कि उसे मुख्य परीक्षा की एक प्रति प्रदान किए बिना, वह पी.डब्ल्यू. 2 की प्रतिपरीक्षा के लिए प्रश्नों को संप्रेषित करने में असमर्थ है। इस पर, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उनसे कहा कि चूंकि मुख्य परीक्षा उनकी उपस्थिति में हुई है, इसलिए वह बयान को पढ़ सकते हैं और फिर जिरह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभियुक्त-याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मुख्य परीक्षा के बयान की प्रति प्राप्त किए बिना जिरह करने में असमर्थता व्यक्त की और विचारण न्यायालय से अनुरोध किया कि गवाह पी.डब्ल्यू.2 की जिरह को सुरक्षित रखा जाये। विद्वत विचारण न्यायालय ने धारा 309 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पी.डब्ल्यू.2 की मुख्य परीक्षा की प्रति प्रदान करने के अनुरोध को स्वीकार करने के बजाय उसे प्रतिपरीक्षा से मुक्त कर दिया क्योंकि पॉक्सो अधिनियम की खंड 33 (2) के तहत यह आवश्यक है कि एक गवाह की प्रतिपरीक्षा से पहले, आरोपी की ओर अंगीकार करना वाला अधिवक्ता पीड़ित को दिए जाने वाले प्रश्नों को विचारण न्यायालय को बताएगा जो बदले में उन प्रश्नों को पीड़ित को बताएगा। विद्वत विचारण न्यायालय

द्वारा पारित दिनांक 29.09.2021 के आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि पी.डब्ल्यू.2 इस मामले में एक स्टार गवाह है और यदि आरोपी-याचिकाकर्ता को जिरह करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह याचिकाकर्ता के मामले को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित करेगा और यह उसके लिए हानिकारक होगा। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक गवाह की प्रतिपरीक्षा का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार है और यदि विचारण न्यायालय द्वारा इससे इनकार किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि न्यायाधीश और निष्पक्ष सुनवाई के हित में, आरोपी याचिकाकर्ता को गवाह पी.डब्ल्यू..2 से जिरह करने का एक और अवसर दिया जा सकता है।

मैंने अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है और पी.डब्ल्यू.2 की मुख्य परीक्षा के साथ-साथ अभियुक्त-याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पी.डब्ल्यू.2 की प्रतिपरीक्षा के लिए विचारण न्यायालय द्वारा इनकार के आदेश को रिकॉर्ड में रखे गए अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ देखा है।

यह ध्यान दिया जाता है कि मास्टर एम ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान में यह कहा है कि वह अपनी वसीयत के लिए वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ गई थी। मास्टर 'एम' को 18 वर्ष का बताया गया है और मास्टर की चिकित्सा जांच से इसकी पुष्टि होती है। 'एम' 17 वर्ष और 11 महीने की आयु दिखा रहा है।

पी.डब्ल्यू..2 की मुख्य परीक्षा की प्रति प्रदान करने के लिए विचारण न्यायालय का इनकार किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। विशेष रूप से, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 211 और 309 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार प्रयोग किया गया विवेकाधिकार न्यायसंगत और उचित था, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है, मामले को प्रतिपरीक्षा के लिए स्थगित करने का विवेकाधिकार केवल विचारण न्यायालय के पास ही हैः-

"231. अभियोजन के लिए साक्ष्यः

(1) इस प्रकार निर्धारित तिथि पर, न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी साक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

(2) न्यायाधीश, अपने विवेकाधिकार पर, किसी भी गवाह की प्रतिपरीक्षा को तब तक स्थगित करने की अनुमति दे

सकता है जब तक कि किसी अन्य गवाह या गवाह की परीक्षा नहीं हो जाती है या किसी गवाह को आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस नहीं ले लिया जाता है।

309. कार्यवाहियों को स्थगित या स्थगित करने की शक्ति

(1) प्रत्येक जांच या मुकदमे में, कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से आयोजित की जाएगी, और विशेष रूप से, जब गवाहों की परीक्षा एक बार शुरू हो जाती है, तो यह दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती है, जब तक कि न्यायालय को कारण दर्ज करने के लिए अगले दिन से आगे का स्थगन आवश्यक न लगे।

(2) यदि न्यायालय, किसी अपराध का संज्ञान लेने या विचारण प्रारंभ करने के बाद, किसी जांच या विचारण के प्रारंभ को स्थगित करना या स्थगित करना आवश्यक या उचित समझता है, तो वह समय-समय पर, दर्ज किए जाने के कारणों से, उसे ऐसी शर्तों पर स्थगित या स्थगित कर सकता है जो वह उचित समझता है, ऐसे समय के लिए जो वह उचित समझता है, और यदि अभिरक्षा में है तो अभियुक्त को वारंट द्वारा रिमांड कर

सकता है, बशर्ते कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के तहत एक बार में पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं भेजेगा, बशर्ते कि जब गवाह उपस्थित हों, तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर, उनकी जांच किए बिना कोई स्थगन या स्थगन नहीं दिया जाएगा और केवल अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित सजा के खिलाफ कारण दिखाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- यदि पर्याप्त सबूत प्राप्त किए गए हैं, यह संदेह उत्पन्न करने के लिए कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया हो सकता है, और यह संभावना प्रतीत होती है कि रिमांड द्वारा और सबूत प्राप्त किए जा सकते हैं, यह रिमांड के लिए एक उचित कारण है।

स्पष्टीकरण 2. जिन शर्तों पर स्थगन या स्थगन दिया जा सकता है, उनमें उचित मामलों में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा लागत का भुगतान शामिल है।"

ज्ञात विचारण न्यायालय ने अभियुक्त याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उसके द्वारा मांगी गई प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से मुख्य परीक्षा की प्रति प्रदान

करने से इनकार करके विवेक का सही उपयोग किया है और इसलिए, कानून की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पी.डब्ल्यू..2 लगभग 18 वर्ष की आयु का है और बी. ए. का छात्र है। द्वितीय वर्ष के साथ-साथ धारा 161 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज अभियोजक का बयान, विशेष रूप से, इस न्यायालय का विचार है कि पूरे तथ्यों पर विचार करते हुए, न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि याचिकाकर्ता को गवाह से जिरह करने का एक अवसर दिया जाता है, जो इस न्यायालय की सुविचारित राय में याचिकाकर्ता को मुकदमे में अपना बचाव करने के लिए एक उचित मौका दिया जाएगा। इस न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनोखीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में (2014 की दाण्डिक अपीलीय में 18 दिसंबर, 2019 को निर्णय लिया गया) की टिप्पणियों में किया है, जो कि इस प्रकार हैः-

> "18. आपराधिक मामलों में निस्संदेह त्वरित निपटान की आवश्यकता होती है और यह स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का हिस्सा होगा। हालांकि, प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास निष्पक्षता के बुनियादी तत्वों और अवसर की कीमत पर नहीं होने चाहिए। अभियुक्त, जिसके

> आधार पर न्यायालय का पूरा आपराधिक प्रशासन स्थापित किया जाता है। शीघ्र निपटारे के प्रयास में, न्याय के उद्देश्य को कभी भी त्याग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्याय का कारण और बुनियादी तत्वों को बनाए रखना सर्वोपरि है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एक मूल विचार और आदर्श के रूप में, प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया की तेजी से निगरानी के परिणामस्वरूप कभी भी न्याय के कारण को दफन नहीं किया जाना चाहिए।"

इसके अलावा, एक अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए (2012) 9 एस. सी. सी. 771 शशिकला बनाम राज्य में एक चेतावनी व्यक्त की, जिसके अंतर्गतः-

> "23.4 हालांकि मुकदमे को जल्द से जल्द निष्कर्ष पर लाने की चिंता को साझा किया जाना चाहिए, यह मौलिक है कि इस प्रक्रिया में कानून के किसी भी अच्छी तरह से स्थापित पूर्व निर्णय का त्याग या समझौता नहीं किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में, न्याय के कारण को पीड़ित नहीं किया जा सकता है, हालांकि, निस्संदेह, यह

अत्यधिक वांछनीय है कि किसी भी मुकदमे की अंतिमता को जल्द से जल्द संभव समय में प्राप्त किया जाए।"

चूंकि पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत मामले की सुनवाई की जा रही है, इसलिए पीड़ित को न्यायालय में लापरवाही से और बार-बार पेश होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए, इस न्यायालय को लगता है कि पी.डब्ल्यू..2 की उपस्थिति हासिल करने के लिए, उसे उचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है। विद्वत विचारण न्यायालय को एक उपयुक्त तिथि पर पी.डब्ल्यू..2 समन करने और याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि याचिकाकर्ता 5,000/- (पाँच हजार रुपये) आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के साथ उपस्थित हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि गवाह पी.डब्ल्यू.2 की प्रतिपरीक्षा के लिए एकल अवसर दिया जाता है और यदि याचिकाकर्ता द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता है, तो उसे आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। Rs.5, 000/- की उक्त राशि का भुगतान पी.डब्ल्यू..2 को अगली तारीख को विचारण न्यायालय में उसकी उपस्थिति के लिए किया जाएगा।

(न्यायाधिपति विनीत कुमार माथुर)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।